

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3576/2010

राजस्थान राज्य, उप-पंजीयक- I, बूंदी के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र श्री बजरंग लाल
2. मुकेश कुमार पुत्र मोहन लाल
3. भगवान लखोटिया पुत्र श्री नंद किशोर
4. मुरली मनोहर पुत्र नंद किशोर
5. शैलेंद्र लखोटिया पुत्र श्री नंद किशोर, भागीदार हाड़ौती राइस मिल्स, गाँव राघवरपुरा, बूंदी।
6. हाड़ौती राइस मिल्स, गाँव राघवरपुरा, तहसील बूंदी, भागीदारों मोहन लाल, मुकेश कुमार, भगवान लखोटिया, मुरलीधर, शैलेंद्र लखोटिया के माध्यम से।

----प्रतिवादी

7. राजस्थान कर बोर्ड, बूंदी।
8. जिला औद्योगिक केंद्र बूंदी, महाप्रबंधक, बूंदी के माध्यम से।

----यथानाम प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री संदीप तनेजा, एएजी,
सुश्री किंजल सुराणा के
साथ।

प्रतिवादी के लिए : श्री दीपक पारेक।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

10/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका राजस्थान कर बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा पारित दिनांक 28.11.2008 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली गई थी।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 10.05.1988 (संलग्नक-ए 2) का पट्टानामा मैसर्स ज्योति जनरल इंडस्ट्रीज, राघवरपुरा, बूंदी तहसील, बूंदी और राज्य सरकार के बीच निष्पादित किया गया था। इसके बाद, दिनांक 10.02.1992 का पूरक पट्टानामा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह रुख अपनाया कि यह एक पूरक पट्टानामा नहीं है और स्टॉप शुल्क की मांग की। व्यथित होकर, प्रतिवादी ने एक पुनरीक्षण दायर किया और उसे बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसलिए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि प्रारंभिक पट्टानामा मैसर्स ज्योति जनरल इंडस्ट्रीज और राज्य सरकार के बीच था, जबकि पूरक पट्टानामा मैसर्स हाडौती राइस मिल्स और राज्य सरकार के बीच था। उनका तर्क है कि यह एक पूरक पट्टानामा नहीं था।
4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया और कहा कि प्रारंभिक पट्टानामा में, यह विशेष रूप से कहा गया था कि लीज पर ली गई भूमि हाडौती राइस मिल्स की स्थापना के उद्देश्य से ली जा रही है और इसलिए, यह एक पूरक पट्टानामा था। यह तर्क दिया जाता है कि

बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए तर्क के अलावा, प्रतिवादी ने मांग को चुनौती देने के लिए अन्य आधार भी उठाए थे।

5. विवादित आदेश के अवलोकन से, यह पता चलता है कि पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दे को विशेष रूप से नहीं निपटाया गया है और विवादित आदेश में यहां तक कि नंगे तथ्यों को भी दर्ज नहीं किया गया है।

6. यह एक स्थापित कानून है कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को एक तर्कसंगत आदेश पारित करना होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान और अन्य के मामले में 2010(9) एससीसी 496 में जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, निम्नलिखित बातें कही हैं:

“क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

ख. एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए।

ग. कारणों को दर्ज करने पर जोर न्याय के व्यापक सिद्धांत की सेवा के लिए है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए।

घ. कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध संयम के रूप में भी कार्य करता है।

ड. कारण यह आश्वासन देते हैं कि निर्णय लेने वाले ने प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों को दरकिनार करते हुए विवेक का प्रयोग किया है।

च. कारण वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अपरिहार्य घटक बन गए हैं, जैसा कि न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सेवा करना।

छ. कारण बेहतर न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं।

ज. कानून के शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवनरेखा है जो इस सिद्धांत को सही ठहराती है कि कारण न्याय की आत्मा है।

झ. इन दिनों न्यायिक या यहां तक कि अर्ध-न्यायिक राय उतनी ही अलग हो सकती हैं जितने कि न्यायाधीश और प्राधिकरण जो उन्हें देते हैं। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो यह दर्शाता है कि प्रासंगिक कारकों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है। यह न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

ञ. कारण पर जोर न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए एक आवश्यकता है।

ट. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मिसाल के सिद्धांत या वृद्धिशीलता के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नहीं।

ठ. निर्णयों के समर्थन में कारण सुसंगत, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का ढोंग या "रबर-स्टैंप कारण" को एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ड. यह संदेह नहीं किया जा सकता है कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर संयम की एक अनिवार्य शर्त है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय लेने वालों को त्रुटियों के प्रति कम प्रवृत्त करती है बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी करती है।

ढ. चूंकि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना गया था।

ण. सभी सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में निर्णय भविष्य के लिए मिसालें स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के

लिए कारण देने की आवश्यकता सार का हिस्सा है और
वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

7. कर बोर्ड का आदेश गैर-सुस्पष्ट है और नतीजतन, इसे रद्द किया जाता है। मामले को बोर्ड को वापस भेजा जाता है ताकि वह पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार नए सिरे से पुनरीक्षण पर निर्णय ले सके।
8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पक्ष बोर्ड के समक्ष सभी दलीलें उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9. आगे की देरी से बचने के लिए, पक्षों को 30.08.2024 को सुबह 11:00 बजे बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने दें।
10. रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

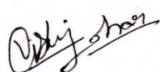
(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

सिंपल कुमावत /14

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़